

प्रधानमंत्री अन्नदाता **आय** संरक्षा अभियान (प्रधानमंत्री-आषा)

| | |
|-----------------------------------|---|
| घोषित | केंद्रीय बजट 2018 |
| वस्तुनिष्ठ | ताकि किसानों को न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) सुनिश्चित किया जा सके। न्यूनतम समर्थन मूल्य में वृद्धि से राज्य के साथ समन्वय में खरीद तंत्र को मजबूत करके किसानों की आय में सुधार हो सकता है। |
| द्वारा लागू किया गया | कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय |
| घटक | 1. मूल्य समर्थन योजना (पीएसएस) 2. मूल्य कमी भुगतान योजना (पीडीपी) 3. निजी खरीद और स्टॉक सूची योजनाओं (पीपीपी) के पायलट |
| मूल्य समर्थन योजना (पीएसएस) | मूल्य समर्थन योजना (पीएसएस), तिलहन और खोपरा की भौतिक खरीद राज्य सरकारों की सक्रिय भूमिका के साथ केंद्रीय नोडल एजेंसियों द्वारा की जाएगी। खरीद के कारण होने वाला खरीद व्यय और नुकसान मानकों के अनुसार केंद्र सरकार वहन करेगी। |
| मूल्य कमी भुगतान योजना (पीडीपीएस) | मूल्य कमी भुगतान योजना (पीडीपीएस) के तहत उन सभी तिलहनों को शामिल करने का प्रस्ताव है जिनके लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य अधिसूचित किया जाता है। इसमें न्यूनतम समर्थन मूल्य और बिक्री/मॉडल मूल्य के अंतर का प्रत्यक्ष भुगतान एक पारदर्शी नीलामी प्रक्रिया के माध्यम से अधिसूचित बाजार प्रांगण में अपनी उपज बेचने वाले पूर्व पंजीकृत किसानों को किया जाएगा। इस योजना में फसलों की कोई भौतिक खरीद शामिल नहीं है क्योंकि किसानों को अधिसूचित बाजार में निपटान पर न्यूनतम समर्थन मूल्य और बिक्री/मॉडल मूल्य के बीच अंतर का भुगतान किया जाता है। |



लीड बैंक योजना

| | |
|---|--|
| शुरू | आरबीआई द्वारा 1969 |
| विवरण | <p>किसी दिए गए जिले के ग्रामीण क्षेत्रों में शाखाओं का अपेक्षाकृत बड़ा नेटवर्क रखने वाले बैंक और पर्याप्त वित्तीय और जनशक्ति संसाधनों से संपन्न बैंक को आम तौर पर उस जिले के लिए अग्रणी जिम्मेदारी सौंपी गई है। इसी के अनुसार देश के सभी जिलों को विभिन्न बैंकों को आवंटित किया गया है।</p> <p>लीड बैंक परिचय के प्रवाह को बढ़ाने के लिए आवंटित जिलों में सभी ऋण संस्थानों के प्रयासों के समन्वय के लिए एक नेता के रूप में कार्य करता है</p> <p>ग्रामीण और अर्धशहरी क्षेत्रों में प्राथमिकता वाले क्षेत्र में शामिल कृषि, लघु उद्योगों और अन्य आर्थिक गतिविधियों के लिए ऋण, भौगोलिक क्षेत्र के संदर्भ में जिले की मूल इकाई होने के साथ ही।</p> |
| लीड बैंक योजना के तहत सौंपे गए बैंक (30 जून, 2020 तक) | 12 सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक 1 निजी क्षेत्र का बैंक कुल जिले: 726 |

LEARNIZY